

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा : एक अध्ययनडॉ० अंकुर कुमार सिंह¹DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.23404824>**Review: 05/09/2026****Acceptance: 11/09/2026****Publication: 16/10/2026**

सारांश : ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) एक प्रमुख भू-राजनीतिक शक्ति बन चुका है, जो विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। 2026 का 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जिसका असर न केवल ब्रिक्स की दिशा पर, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। यह अध्ययन सम्मेलन के बहुआयामी प्रभाव का विश्लेषण करेगा, जिसमें आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय स्थिरता और तकनीकी सहयोग शामिल हैं। बदलते भू-राजनीतिक तनाव और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के चलते, सम्मेलन काफी संवेदनशील है। भारत की अध्यक्षता में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में प्लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया और टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से, भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में सक्रियता दिखाई। 2026 का सम्मेलन व्यापक सुरक्षा मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को आकार देगा।

मुख्य शब्द— यातायात प्रतिबंध, वैश्विक शासन, गैर-पारंपरिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा।

परिचय

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक शक्ति बन चुका है, जो वैश्विक शासन में विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। 2026 में होने वाला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसका प्रभाव न केवल ब्रिक्स की भविष्य की दिशा पर पड़ेगा, बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी। यह अध्ययन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन के बहुआयामी प्रभाव का विश्लेषण करेगा, जिसमें आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय स्थिरता और तकनीकी सहयोग शामिल हैं। ब्रिक्स के भीतर बदलते भू-राजनीतिक तनाव, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों की बढ़ती महत्वपूर्णता, इस शिखर सम्मेलन को संवेदनशील बना देती है। भारत की BRICS में अध्यक्षता, जिसके तहत शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण है।¹

शिखर सम्मेलन की थीम "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" थी। इसमें भाग लेने वाले नेताओं ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर संवाद किया और एक सर्वसम्मत दस्तावेज "नई दिल्ली घोषणा" को अपनाया, जो 140 अनुच्छेदों में वैश्विक शासन सुधार, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, व्यापार, वित्त, ऊर्जा, जलवायु नीति, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कृषि आदि को कवर करता है।² भारत ने आतंकवाद, विशेषकर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और टेरर फंडिंग के खिलाफ सख्त

¹ रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन

कार्रवाई पर जोर दिया। यह सम्मेलन, भारत की कूटनीति में आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने का अवसर रहा। सम्मेलन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत ने यह स्पष्ट किया कि ब्रिक्स कोई पश्चिम-विरोधी मंच नहीं है, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और सुरक्षा हितों का संतुलन बना रहा। इसके अतिरिक्त, द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से, विशेषकर चीन सहित अन्य देशों के साथ, भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई। इस प्रकार, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन न केवल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच रहा, बल्कि इसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा।³ इस प्रकार, 2026 में शिखर सम्मेलन भारत का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच होगा, जो कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर प्रभाव डालेगा।

स्वागत एवं विश्लेषण

अंतर्राष्ट्रीय कवरेज में ब्रिक्स समूह के भीतर मतभेदों के बावजूद सर्वसम्मति से घोषणापत्र पर पहुँचने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। रॉयटर्स के अनुसार, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के भिन्न रुख के कारण नई दिल्ली के लिए यह कार्य चुनौतीपूर्ण था। मई में विदेश मंत्रियों की बैठक में युद्ध पर मतभेदों के परिणामस्वरूप कोई संयुक्त विज्ञप्ति नहीं जारी की गई थी। एसोसिएटेड प्रेस ने शिखर सम्मेलन को BRICS सदस्यों के पश्चिमी प्रभुत्व के प्रति विरोध के रूप में देखा और भारत के संतुलन बनाने के प्रयासों को रेखांकित किया।⁴ फाइनेंशियल टाइम्स ने "खाड़ी शांति के प्रयास" पर टिप्पणी की, लेकिन भारत-चीन प्रतिस्पर्धा को सामंजस्य के लिए बाधा बताया। बीबीसी ने बताया कि चीन, रूस, और ईरान समूह का उपयोग पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए करना चाहते हैं, जबकि भारत इसे पश्चिमी विरोधी गुट के रूप में पेश नहीं करना चाहता। सी. राजा मोहन ने भारत के दृष्टिकोण को "कोई उग्रता नहीं" के तहत वर्णित किया, जिसमें व्यावहारिक सहयोग पर जोर दिया गया।⁵

द गार्जियन ने भारत की प्राथमिकता और शी की यात्रा को भारत-चीन संबंधों की अस्थायी नरमी के रूप में दर्शाया। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने चीन-भारत आर्थिक विभाजन का जिक्र किया, जिसमें आर्थिक असंतुलन का उल्लेख किया गया। यह सम्मेलन विभिन्न सरकारों के लिए एक साझा आधार खोजने का प्रतीक बना, जिसमें घोषणापत्र में अमेरिका की नीतियों की बिना नाम लिए आलोचना की गई। बीबीसी ने बताया कि घोषणापत्र में 2026 के ईरान युद्ध के संदर्भ में किसी पर भी दोष नहीं मढ़ा गया। अल-जज़ीरा ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चिमी नेतृत्व वाली व्यवस्था के प्रति साझा असंतोष को एकीकृत भू-राजनीतिक कार्रवाई में बदलने में कठिनाइयाँ हैं, भले ही ईरान युद्ध का प्रभाव महत्वपूर्ण हो।

वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में हो रहे बदलाव और ब्रिक्स की भूमिका

वैश्विक सुरक्षा वातावरण कई कारकों से प्रभावित है, जैसे भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता, क्षेत्रीय संघर्ष, आतंकवाद, साइबर युद्ध और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। इस संदर्भ में, ब्रिक्स विकासशील देशों के लिए एक मंच बना है जहाँ वे अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकते हैं और सामूहिक रूप से चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। 2026 में होने वाला 18वां शिखर सम्मेलन अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में होगा। ब्रिक्स एक स्थिर और समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके सदस्य वैश्विक शासन संस्थानों

में सुधारों की वकालत कर सकते हैं। भारत के लिए, यह मंच पश्चिमी देशों के प्रभुत्व से बाहर प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उसे अपनी रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लाने और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलती है। 2026 का शिखर सम्मेलन भारत के लिए वैश्विक सुरक्षा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

सुरक्षा और रसद

भारतीय अधिकारियों ने नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया, जिसमें लगभग 30,000 पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। सुरक्षा में घेराबंदी, ड्रोन रोधी प्रणालियाँ, निगरानी कैमरे और यातायात प्रतिबंध शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल विभिन्न होटलों में ठहरे, उच्च स्तरीय आवागमन के दौरान सड़क मार्ग पर परिवर्तन और अस्थायी प्रतिबंध लागू किए गए, और निवासियों को दिल्ली मेट्रो के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया।⁶

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताएँ

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का परिदृश्य आंतरिक और बाह्य खतरे दोनों से प्रभावित है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध मुख्य बाहरी चुनौतियाँ हैं। चीन के साथ सीमा विवाद और हिंद-प्रशांत में उसकी आक्रामकता दीर्घकालिक चुनौती है, जबकि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। आंतरिक सुरक्षा में उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद और सांप्रदायिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, भारत गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि साइबर युद्ध और इसके प्रभाव। तकनीकी उन्नति, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, युद्ध में नए आयाम जोड़ रही है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट, जैसे जल संकट और पर्यावरणीय गिरावट, नई सुरक्षा कमजोरियों को जन्म दे सकते हैं।

इस संदर्भ में, भारत के लिए अनेकता और विकास की आकांक्षाओं के साथ सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत को सामूहिक समाधान और बेहतर समझ बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 : भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अवसर

2026 में होने वाले 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के कई अवसर प्रस्तुत करता है। यह चीन के साथ रणनीतिक संवाद और विश्वास-निर्माण उपायों को बढ़ावा देने का एक मंच है। ब्रिक्स के अंदर लगातार जुड़ाव से गलतफहमियों को कम किया जा सकता है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को घटा सकता है। भारत इस अवसर का उपयोग सीमा प्रबंधन मानकों के पालन की वकालत करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। यह सम्मेलन आतंकवाद विरोधी सहयोग का भी एक मंच बन सकता है, जहाँ साझा खतरों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जा सकती है। खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त प्रशिक्षण, और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए रणनीतियों के विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत का लक्ष्य वैश्विक शासन सुधारों में अपने हितों को आगे बढ़ाना भी है, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव मिले। ब्रिक्स एक सामूहिक आवाज के रूप में

न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की वकालत कर सकता है, जो भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करेगी। अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार और अंतरिक्ष अन्वेषण में ब्रिक्स सहयोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत कर सकता है। आर्थिक समृद्धि रक्षा आधुनिकीकरण और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। अंत में, ब्रिक्स का विस्तार विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बना सकता है, जिससे भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को और भी प्रभावी ढंग से बढ़ा सकेगा।⁷

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ और जोखिम

18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों और जोखिमों का सामना करता है। सबसे बड़ा खतरा चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामकता से है, जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंच सकता है या उसे प्रतिकूल समझौते करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा ताकि ब्रिक्स चीन की वर्चस्ववादी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा न दे। सदस्यों के भिन्न-भिन्न रणनीतिक हित और विदेश नीति प्राथमिकताएँ भी समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं। रूस-यूक्रेन संघर्ष या मध्य पूर्व की स्थिति जैसे मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोण सुरक्षा एजेंडा के विकास में बाधा डाल सकते हैं। ब्रिक्स को पश्चिमी विरोधी गठबंधन के रूप में देखे जाने से भारत के लिए राजनयिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे उसे संतुलन बनाए रखना होगा।

इसके अतिरिक्त, सीमा विवाद और क्षेत्रीय संघर्ष पर ब्रिक्स की प्रभावशीलता सीमित है, क्योंकि उसकी मुख्य शक्ति आर्थिक सहयोग में है। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए केवल ब्रिक्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने रक्षा आधुनिकीकरण को जारी रखना और अपने गठबंधनों को मजबूत करना चाहिए। सदस्यों की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ भी भारत के हितों को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सदस्य देशों को अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना प्रभावों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करना आवश्यक होगा।⁸

भारत के लिए शिखर सम्मेलन से सुरक्षा संबंधी अधिकतम लाभ प्राप्त करने की रणनीतियाँ

भारत को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का लाभ उठाने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। **पहले**, उसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों पर सहयोग को गहरा करने की प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन शामिल हैं। भारत इन क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकता है। **दूसरे**, भारत को वैश्विक शासन में सुधार के लिए अपने दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए, ब्रिक्स मंच का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय कानून, विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और बहुध्रुवीयता का समर्थन करना चाहिए। **तीसरा**, भारत को ब्रिक्स में चीन के साथ संबंधों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। संवाद और सहयोग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसे अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंध भी मजबूत करने चाहिए। **चौथा**, भारत को आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए ब्रिक्स देशों का लाभ उठाना चाहिए, जिसमें व्यापार, निवेश और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग शामिल है। **पाँचवें**, भारत को ब्रिक्स के संस्थागत तंत्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो बेहतर समन्वय और निर्णय कार्यान्वयन की ओर ले जाएगा। अंत में, भारत को ब्रिक्स के अंदर विविध हितों और दृष्टिकोणों को संभालने के लिए कुशल कूटनीति अपनानी होगी, जिससे समूह के ध्रुवीकरण को रोका जा सके। यह भूमिका ब्रिक्स की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण हो सकती है।

निष्कर्ष

2026 में होने वाला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूरगामी प्रभावों वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में हो रहे बदलावों के इस दौर में, यह शिखर सम्मेलन अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। भारत के लिए यह रणनीतिक संवाद को गहरा करने, आतंकवाद-विरोधी सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक शासन सुधारों की वकालत करने और अपनी सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग का लाभ उठाने का एक उपयुक्त अवसर है। हालांकि, चीन का बढ़ता प्रभाव, सदस्य देशों के हितों में भिन्नता और बाहरी ध्रुवीकरण की संभावना एक सतर्क और रणनीतिक दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाती है। भारत को ब्रिक्स के भीतर रणनीतिक रूप से सक्रिय रहते हुए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सक्रिय रूप से अपनी राह तय करनी होगी। एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाकर, प्रमुख सुरक्षा अनिवार्यताओं को प्राथमिकता देकर और कुशल कूटनीति का प्रयोग करके, भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लाभों को अधिकतम कर सकता है, जिससे उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिक स्थिर एवं समृद्ध वैश्विक व्यवस्था में योगदान मिलेगा। यह शिखर सम्मेलन जटिल भू-राजनीतिक धाराओं को समझने और अपने चिरस्थायी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हुए बहुपक्षवाद के भविष्य को आकार देने की भारत की क्षमता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।

संदर्भ

"ब्रिक्स इंडिया 2026", ब्रिक्स इंडिया 2026, भारत सरकार, 12 सितंबर 2026।

"ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा : लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण"। प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, 12 सितंबर 2026, पब्लिक टेक्नोलॉजीज के माध्यम से 12 सितंबर 2026।

"18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 : भारत मंडपम में नेताओं की बैठकों और प्रमुख सत्रों का पूरा कार्यक्रम देखें", बिजनेस टुडे, 9 सितंबर 2026, 12 सितंबर 2026।

"मोदी के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में ट्रंप के विरोधियों को मिली साझा ज़मीन", ब्लूमबर्ग न्यूज़, 12 सितंबर 2026।

मोशीरी, आज़ादेह (13 सितंबर 2026), "ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 दिल्ली : ईरान युद्ध ने संबंधों को नया आकार दिया लेकिन मतभेदों को उजागर किया", बीबीसी न्यूज़, 14 सितंबर 2026।

"ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : दिल्ली में यातायात मार्ग, होटल और पुलिस व्यवस्था", द इंडियन एक्सप्रेस, 10 सितंबर 2026।

"ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा : लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण", प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, 12 सितंबर 2026।

"ब्रिक्स 2026 : भारत मंडपम में 37 भारतीय डीप-टेक नवप्रवर्तकों ने प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया", डीडी इंडिया, 11 सितंबर 2026।